श्री सभापति : मिस्टर बसु, देखें कि इन्होंने जो एशोरेंस दिया है उस पर क्या काम करते हैं।

*63. [The questioner (Shri C. Rama Chandraiah) was absent for answer *vide* page *36 infra.]*

Education For All-Global monitoring report

*64. PROF. SAIF-UD-DIN SOZ .††
DR. MANMOHAN SINGH :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether he is aware of the fact that UNESCO's, latest Education For All (EFA) global monitoring report says that Bangladesh has achieved gender parity equal enrolment of boys and girls at school at Primary level and India scraps the bottom of the list just a little above Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The gender parity index of Primary education shown for India (based on data for the year 1999-2000) is 0.83, for Bangladesh is 0.97 and that of Pakistan 0.74. The Ministry of Human Resource Development have conveyed their disagreement with regard to the conclusions drawn in the EFA Global Monitoring Report-2003 that India is at risk of not achieving gender parity by 2015 at the primary stage, even before its release. The conclusions have been based on projections made primarily on old data and not taking into account the updated, though partial, data supplied by this Ministry. UNESCO Institute of Statistics (U!S) has been requested to fine-tune their estimation methods to include updated survey data and not wait for disaggregated Census data.

The other International agencies like UNICEF and World Bank, which have accepted the National Family Health Survey (NFHS) data, have also endorsed India's viewpoint of having made significant progress towards achieving the goal of gender parity by 2015...In the Global Monitoring Report itself, there is mention of the fact that there are already

††The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Saif-ud-Din Soz.

policies/programmes in place in many of the "at risk" countries, that could deliver parity within a few years. At the launch of the Report in New Delhi, the Director of the Monitoring Report team had also explained that the Report had made projections based on the data available and that countries like India had put in place targeted interventions through the *Sarva Shiksha Abhiyan* that could move it closer to attaining parity. UIS have also indicated that they would be taking steps to include survey data and build flexibility in their modeling system, so that they do not have to wait for disaggregated Census data alone. Lastly, the communique issued at the end of the High Level Group Meeting also calls for enhancing the capacity of UIS for identifying data gaps and for improving data collection and quality.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Chairman, I feel a little disappointed with the reply that the hon. Minister has Tabled. Sir, it is customary for many Ministers to lump question-answers together in a statement. But I expected it differently from Dr. Joshi. As far as UNESCO is concerned, EFA was prepared by a very established forum at the UNESCO, enjoying international reputation. The hon. Minister went to Paris, of course, for work and conferences a number of times, and he should have kept a track of what EFA was doing. Now, the hon. Minister should explain to the House whether his five-year term has made any difference in the realm of education. Now, it does not do us any pride. We cannot feel proud of lumping together of India with countries like Chad, Yemen, Guinea, Pakistan. These were Dakar goals. I think, perhaps, he was present at Dakar in 2000 where goals like universal primary education, adult literacy, quality education and gender equality were set. I think, as a student of education, in all the four areas, we have not made any spectacular progress. The hon. Minister, in his answer, has said that there are gaps in statistics.

श्री सभापति : सिर्फ क्वेश्चन कीजिए ।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I cannot say that he is next to any Minister in the world. He knew what the UNESCO was doing. He could have taken up the *Sarva Shiksha Abhiyan* and fought the battle. But, even so, on 7th November, this Report EFA was released to the Press in Delhi. Still the Minister...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: My question is this. Is he not raising an alarm for the country that we are lagging behind in gender equality and we are behind Bangladesh? In his answer, the hon. Minister mentioned about Bangladesh also.

श्री सभापति : वह ठीक है।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: The gender parity index of primary education for India is 0.87 per cent. He compares it with Bangladesh's 0.97 per cent, and feels satisfied that we are close to Bangladesh. That will not do any proud to you. That is the point.

श्री सभापति : अब आप बैठिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए । When are you raising alarm?

डा. मुरल मनोहर जोशी : कृपया, इस प्रश्न का गहराई से उत्तर सुनें ।

श्री सभापति : मेरा टाइम चला जाएगा ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं नहीं जानता । इन्होंने सदन में कहा है कि यह देश के ऊपर बड़ा कलंक है, मुझे इसे धोने की जरूरत है और जो कंलक ये लगा रहे हैं उसे भी साफ करने की जरूरत है। यूनेस्को के साथ हमारा संघर्ष पिछली रिपोर्ट से बराबर चल रहा है। हमने उनसे कहा है, इस बार भी कहा है कि आपके आंकडे गलत है । यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. हमारे जिन आंकडों को मानते हैं आप उन्हें नहीं मान रहे हैं। हमने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने आंकडों की स्थिति को सुधारेंगे, इसका हमें इस बार वचन दें । वे 1998 और 1999 के आंकडों के आधार पर अपनी सारी जांच बता रहे हैं । हमारी जो 2001 की सेंसस हैं, जनगणनी है उसके आंकडों के आधार पर इसे मानने के लिए वे तैयार नहीं है। इसका हम उनसे बराबर आग्रह कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने उन्हें मई के महीने में, मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में आगाह किया था कि आप फिर वही गलती करने जा रहे हैं । मैंने ही नहीं कहा बल्कि यहां नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उसमें अनेक देशों ने हमारा साथ दिया। इस बार उन्होंने, डायरेक्टर जनरल ने यह स्वीकार किया कि वे अपने आंकडों को आगे से अधिक सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। इस बारे में यह स्थिति केवल इसी कारण से हैं कि वे पुराने आकंडे लेते हैं । जैसे किसी जमाने में यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. में यह कहा जाता था कि हिन्दुस्तान का लिटरेसी रेट केवल 52 प्रतिशत है । बरसों तक यही चलता रहा, 1998 में भी यही चल रहा था। हमने कहा कि यह क्या मामला है ? हमने सर्वे कराया और उन्हें बताया कि यह इतना नही है, यह 62 प्रतिशत है और अब 2001 की सेंसस में 66 प्रतिशत हैं । पहली बार हिन्दुस्तान में तीन करोड़ लोगों का निरक्षता से एब्सोल्यूट नम्बर कम हुआ है। यूनेस्कों ने खुद हमे दो-दो बार

महिला शिक्षा के लिए "नोमा" पुरस्कार दिया है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अंततोगत्वा उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा है कि आंकडों के मामले में यह जो डिस्पैरिटी है, यह जो अंतर है यह इसकी वजह से है। हमने उन्हें अपने सारे प्रोजेक्शन दिए है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इसमें कोई राजनीति मत कीजिए बल्कि सब मिलकर इसे दूर कीजिए। विभिन्न राज्यों के साथ हम बराबर संपर्क रखे हुए है कि कहां-कहां इसमें दिक्कत आ रही है। अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 2003 में एक नई स्कीम चालू की है जिसमें महिला और पुरूष के अंतर को बिल्कुल समाप्त करने के लिए हम आगे बढे। हम इस सवाल पर बहुत पहले से ध्यान दे रहे हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा इंडेक्स जो 0.41 था वह बढकर 0.82 **हो गया है बल्कि 0.83 हो गया है । अपने** आप में प्रगति की निशानी है। 0.17 के लिए ये कहते है कि आप पन्द्रह बरस तक नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा अन्याय और गलत बात हिन्दुस्तान के लिए नहीं हो सकती।

इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप अपनी बात को सुधारिये, यूनेस्कों की जो दूसरी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 8 राज्यों का सर्वेक्षण किया है उसमें वे तारीफ के पुल बांधते है। हमने सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दी है, दुनिया के सामने रख दी है और यूनिसेफ की रिपोर्ट अभी आने वाली है, 10 दिसम्बर को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब आम देखेंगे कि उन्होंने हमारे इस सारे कार्यक्रम की कितनी प्रशसा की है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अखबारों मे छपी हुई खबरो से परेशान मत होइए। अगर आप हमसे सम्पर्क कर लेते तो हम आपको सारा पत्राचार और सारी चीजें दिखा देते। मैं वे सारे पत्र पढ कर सुना देता हूं।

श्री सभापति : ये सारे पत्राचार और प्रति इनको भेज दीजिए। प्रश्न संख्या – 65

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सप्लीमेंट्री तो होने दीजिए।

श्री सभापति : आपने एक सप्लीमेंट्री में कई सवाल कर दिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : दूसरा हिस्सा है सवाल का।

श्री सभापति : दूसरा क्या हिस्सा है?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं आपको बतलाता हूं।

MR. CHAIRMAN: You can put a straight question... *(Interruptions)...*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं तो जोशी साहब को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बडे कांफिडेंस से बोला। मगर मैं इनको यह कहता हूं कि आप यह कहते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, सब ठीक होगा। उसी तरह मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। इस वक्त आपको बंगलादेश, गिनी, यमन और पाकिस्तान के साथ मिलाया गया है। मैं कहता हूं कि इंडिया को उनके साथ मिलाया जाए।

We should compare with Germany, England and other such countries, which are advanced in the field of education. ...*(Interruptions)*...
We have a very vast scientific infrastructure. We should utilise it. Now if you feel that much confident...*(Interruptions)* आप अखबार से लेते हैं, यह अखबार नहीं है।

श्री सभापति : मैं अब एलाउ नहीं करूंगा। Mr. Soz,! will not allow. *(Interruptions)..* **प्रो.o सैफुद्दीन सोज :** अगर आप यूनेस्को से यह मामले उठाएंगे और आकंडों को दुरूस्त करेंगे तो आप इस सदन में आकर हाऊस को कांफिडेंस में लेकर ये सारी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करेंगे ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपकी आशंकाए बरबार दूर कर दी है । और आप निश्चित रहिए कि ये सारी आशंकाएं बिल्कुल बेबुनियाद है और पिछली बार भी सन् 2000 की रिपोर्ट में यही बात आई थी तब भी हमने उनसे यह कहा था कि आप ये आकंडे गलत ले रहे हैं और आज फिर हमने उनसे कहा है और बराबर उनको कहते हैं । आपने यह कहा है कि हम उनसे कम्पेयर करेंगे, आप यकीन मानिए वह बिल आने वाला है जबकि जर्मनी, इंग्लैड, फ्रांस हमसे कम्पेयर करेंगे।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has highlighted the great importance of ensuring gender parity in access to education. This is a matter in which there can be no difference of opinion among the Members of the House. I would like to ask the Minister whether he is aware that lack of toilets separately for girls is a major obstacle in many parts of the country, which keeps the girl child away from school. ff so, what is being done to make good this deficiency?

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसकी तरफ हमने पूरा ध्यान दिया है । एक तो जो नई स्कीम बनाई है जिसमें महिला शिक्षक के ऊपर महिला बालक के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है, उसी को टारगेट करके किया गया है कि उसमें जो भी सामाजिक अवरोध है उनको भी दूर किया जाए और उन बच्चियों को **पढ़ाने** के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाए । यहां तक कि जो बच्चियां कई बार किसी कारण से स्कूलों में नहीं आ पाती है कि उनकी सुरक्षा का सवाल उठता है तो उनके लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि इनके लिए छात्रवास बना दिए जाए जिससे वे वहां रह सकें और वहां बराबर पढती रहे। सर्व शिक्षा अभियान में और **अभी** संविधान में हमने जो संशोधन किया है उसमें भी यह व्यवस्था है कि बालक और बालिका में कोई अंतर नहीं होगा । जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में उसकी प्रतिलिपि मैं आपके पास भेज चुका हूं , उसमे भी यह पूरी जिम्मेदारी दी गई हैं कि बालक और बालिका में कोई फर्क नहीं होगा और अगर

उसमें आपके कोई और सुझाव होंगे जो इस कानून को और अच्छा व बेहतर बना सकेंगे सरकार उनका स्वागत करेगी और उनको शामिल करेगी । इस मामले में कोई भी सुझाव, कोई भी व्यवस्था जो मेरे सामने रखी जाएंगी जिससे बालक और बालिका के बीच में यह अंतर समाप्त हो मैं उसका खुले दिल से स्वागत करूंगा और पूरी मदद करूंगा ।

Objectives of National Education Policy

*65. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the trend of public expenditure on education expressed as a percentage of GDP and total public expenditure since 1990; and

(b) whether this trend is consistent with the resource requirements for meeting the National Education Policy objectives?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A Statement-I indicating the total public expenditure and expenditure on education and other Departments as percentage of GDP from 1990-91 to 2002-03 is enclosed. (See below)

From the statement it may be observed that the total expenditure on education has increased from Rs. 19615.85 crore in 1990-91 to Rs. 88919.00 crore in 2002-03 (Budget Estimate) to meet the requirement of various educational schemes/projects.

Statement-I

Objectives of National Education Policy

(Rs. in crore)

Year	Total Public Expenditure	Expenditure* On Education & other Deptts.	Expenditure On Education &other Deptts. as % age of GDP
1	2	3	4
1990-91	146711.53	19615.85	3.84
1991-92	170370.38	22393.69	3.80
1992-93	190327.49	25030.30	3.72